कंपनियों को विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से लाइसेंस मिलेगा

रियल एस्टेट में 39406 करोड़ के निवेश से 20 हजार को रोजगार

खास

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार एक बार फिर यूपी में निजी क्षेत्रों में हाईटेक टाउनशिप योजनाएं शुरू कराने जा रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले इसके लिए निजी कंपनियों को करार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनियों द्वारा किए जा रहे करार के मुताबिक योजना की लागत और उससे लोगों को मिलने वाले रोजगार के बारे में भी जानकारियां दी जा रही हैं। अब तक 10 बड़ी कंपनियों से करार हो चुका है जिसमें 39406 करोड़ के निवेश से 20 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है।

लाइसेंस लेकर स्वयं लेंगी जमीन

निजी क्षेत्र में आने वाली कंपनियों को करार के आधार पर विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से लाइसेंस दिलाया जाएगा। इसके लिए उन्हें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना होगा और इसमें बताना होगा कि उनके द्वारा कितनी जमीन कहां पर ली जा रही है। इसमें उन्हें यह भी बताना होगा कि कितने वर्षों में वे परियोजनाओं को पूरी करेंगी। तय समय के आधार पर परियोजनाओं को पूरा करना होगा। यह भी शपथ पत्र देना होगा कि आवंटियों को कितने समय में मकान या भूखंड पर कब्जा दिया जाएगा।

दूर होगी आवासीय समस्याएं: राज्य सरकार का मकसद शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की आवासीय समस्याओं का समाधान कराना है। विकास प्राधिकरणों के साथ ही निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोड़ी-बड़ी कंपनियों को निवेश का मौका दिया जा रहा है। बड़े मकानों के साथ ही छोटे मकानों को भी बनाया जाएगा। गरीब और निम्न मध्य वर्ग के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मकान बनाए जाएंगे। कुल क्षेत्रफल में यह 20 प्रतिशत होगा।

20 फीसदी क्षेत्र में ईडब्ल्यू एस व एलआईजी मकान बनाए जाएंगे

इन शहरों में कंपनियों को दी गई परियोजनाएं

कंपनी	प्रोजेक्ट	खर्च करोड़ में	रोजगार	शहर
गोदरेज	गोल्फ लेख	17500	13000	गौतमबुद्धनगर
अंसल	टाउनशिप	4750	800	बुलंदशहर
उप्पल चढ्डा	टाउनशिन	3150	900	गाजियाबाद
अभिनंदन लोढ़ा	टाउनिशन	3000	1200	अयोध्या, वाराणसी गोरखपुर
ओमेक्स	टाउनशिप	1700	1000	आगरा
गोदरेज	गोल्फ कोर्स	1000	2500	गौतमबुद्धनगर
ओमेक्स	आवासीय प्लाट	850	500	लखनऊ
मोहित दादू	टाउनशिप	21	23	आगरा
रेड ओरियन	टाउनशिप	8200	1000	----

शहर का बदलेगा स्वरूप

आवास विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि निजी क्षेत्रों के माध्यम से हाउसिंग सोसायटियां विकसित होने से शहर का स्वरूप भी बदलेगा। हाईटेक टाउनशिप शहर के बाहर बसेंगी। इससे जहां रोजगार के संसाधन बढ़ेंगे, वहीं पर शहरों का स्वरूप भी बदलेगा। सड़क के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार वर्ष 2024 तक सभी जरूरतमंदों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है।